डॉ. (श्रीमती) शिप्रा

बनाम

शांति लाल खोईवाल,

निर्णय दिनांक 3 मार्च, 1996

उद्धरण: 1996 एआईआर 1691, 1966 एसएससी(5) 181, जेटी

1996(5) 681, 1996 स्केल(3) 369

बैन्च-के.रामास्वामी, एस.पी. भरूचा और के.एस.परिपूर्णन, जे.जे.

आदेश।

चूंकि इसमें शामिल प्रश्न सभी अपीलों में सामान्य हैं, इसलिए उन्हें एक साथ निपटाया जाता हैं।

प्रथम अपील, अर्थात सी.ए. 1994 की संख्या 6359, 1994 की चुनाव याचिका संख्या 6 में दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 30 अगस्त 1994 के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं। अपीलकर्ता का नामांकन संगति संख्या 1 से, अर्थात, राजसमन्द, राजस्थान राज्य की 10 वीं विधान सभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं हैं। मतदान के बाद प्रतिवादी के चुनाव को अपीलकर्ता ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि प्रतिवादी ने भ्रष्ट आचरण किया था। नोटिस की तामील

के बाद, प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं, जिसमें नोटिस की प्रति के साथ समर्थन में हलफनामा भी शामिल था। चुनाव याचिका यानी, अनुलग्नक 5 और 6, जो उसे दी गई थी, में नोटरी द्वारा सत्यापन शामिल नहीं था; इसलिए चुनाव याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 83(1)(सी) के अनुसार सुनवाई योग्य नहीं थी। आपत्तियों को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, जिसने तदनुसार 30 अगस्त, 1994 के आक्षेपित आदेश द्वारा चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।

1994 के सीए संख्या 8080 में, राजस्थान राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 152, अर्थात, सहाड़ा के लिए चुनाव 11 नवंबर को हुए थे और प्रतिवादी को 28 नवंबर, 1993 को निर्वाचित घोषित किया गया था। चुनाव हारने के बाद अपीलकर्ता ने 1994 की चुनाव याचिका संख्या 4 दायर की, जिसमें कथित तौर पर उसके द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के आधार पर प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती दी गई थी।

श्रीमती शिप्रा के मामले के समान, प्रतिवादी को प्रदान की गई चुनाव याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे की प्रति में नोटरी द्वारा सत्यापन शामिल नहीं था।

जब प्रतिवादी द्वारा उस संबंध में आपत्ति उठाई गई, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने 22 सितंबर, 1994 के फैसले द्वारा चुनाव याचिका खारिज कर

दी।

1995 के सी.ए. संख्या 6635 में, राजस्थान राज्य की 10वीं विधान सभा के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 160, अर्थात, पाली जिले के रायपुर में चुनाव हुए। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसे 28 नवंबर, 1993 को निर्वाचित घोषित किया गया था। चुनाव हारने के बाद अपीलकर्ता ने 1994 की चुनाव याचिका संख्या 9 दायर की, जिसमें प्रतिवादी द्वारा यहां किए गए भ्रष्ट आचरण के आधार पर प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती दी गई। इसी तरह की पिछली अपीलो में, प्रतिवादी को चुनाव याचिका के साथ प्रदान की गई हलफनामें की प्रति में नोटरी द्वारा सत्यापन शामिल नहीं था। जब प्रतिवादी द्वारा उस संबंध में आपत्ति उठाई गई, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26 मई, 1995 के आक्षेपित निर्णय द्वारा आपत्ति को बरकरार रखा और चुनाव याचिका खारिज कर दी।

1993 की सिविल अपील संख्या 200 में, प्रतिवादी को मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। अपीलकर्ता, एक निर्वाचक, ने 1991 की चुनाव याचिका संख्या 9 दायर की, जिसमें प्रतिवादी द्वारा उसके द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए उसके चुनाव को चुनौती दी गई। प्रतिवादी को प्रदान की गई हलफनामें की प्रति में नोटरी या शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापन शामिल नहीं था। जब प्रतिवादी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे बरकरार रखा और

चुनाव याचिका खारिज कर दी।

अभीनिर्धारित: इस प्रकार सभी अपीलों में, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उठता है: क्या चुनाव याचिका की प्रतिलिपि, समर्थन शपथ पत्र के साथ, संबंधित उत्तरदाताओं को चुनाव आचरण नियमों के नियम 94-ए के तहत निर्धारित फॉर्म 25 के साथ प्रदान की गई थी, 1961 (संक्षेप में, जिला मजिस्ट्रेट/नोटरी/शपथ आयुक्त द्वारा विधिवत सत्यापित सत्यापन भाग के बिना 'नियम' को चुनाव याचिका की "सच्ची और सही प्रतिलिपि" कहा जा सकता हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 81(3) में परिकल्पित हैं। अधिनियम की धारा 81(1) के तहत प्रस्तुत किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने वाले चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता हैं, जिसमें कथित भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण दिया गया हैं, जिसमें "पूर्ण" भी शामिल है। इस तरह के भ्रष्ट आचरण करने वाले कथित दलों के नाम और ऐसे प्रत्येक आचरण के कमीशन की तारीख और स्थान का यथासंभव विवरण; और चुनाव याचिकाकर्ता याचिका पर हस्ताक्षर करेगा और दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित तरीके से सत्यापन करेगा।

धारा 81 की उप-धारा (3) में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक चुनाव स्थिति के साथ उसकी उतनी ही प्रतियां संलग्न होगी, जितनी चुनाव याचिका में उल्लिखित उत्तरदाताओं की हैं और ऐसी प्रत्येक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत सत्यापित की जाएगी।" "याचिका की सच्ची प्रति" हो। निर्विवाद रूप से, सम्मन के साथ चुनाव याचिका की प्रतियों की अपेक्षित संख्या को अपीलकर्ता ने अपने हस्ताक्षर के तहत सच्ची प्रति के रूप में सत्यापित किया था।

प्रतिवादी को प्रदान की गई प्रति में यह स्वीकार किया गया कि उसमें सत्यापन भाग नहीं था। नियमों के नियम 94-ए में यह प्रावधान हैं कि भ्रष्ट आचरण के आरोपों वाला हलफनामा निर्धारित प्रपत्र में होगा, अर्थात, फॉर्म 25 जिसमें चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित कथित भ्रष्ट आचरण की शुद्धता की विधिवत पुष्टि करने के लिए शपथ पत्र के साथ शामिल होने का आदेश दिया गया हैं। चुनाव याचिका के विभिन्न पैराग्राफों में और जिला मजिस्ट्रेट/नोटेरी/शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापन किया गया हैं। प्रतिवादी को प्रदान की गई प्रतिलिपि में नोटेरी द्वारा ऐसा कोई सत्यापन शामिल नहीं था, जिसने चुनाव याचिका के साथ दायर मूल हलफनामे को प्रमाणित किया था कि यह एक सच्ची प्रतिलिपि हैं। सवाल यह उठता हैं कि अभिव्यक्ति सच्ची प्रतिलिपि के अर्थ के बारे में हैं। "साक्ष्य पर सरकार" (14 वाँ संस्करण -1993) में "परिशिष्ट ए" के तहत पृष्ठ 2183 पर कहा

गया

हैं कि एक हलफनामा किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर लिखित रूप से दिया गया एक बयान हैं, जिसके पास शपथ या प्रतिज्ञान देने का अधिकार हैं। हलफनामा नियम 94-ए के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म 25 में होना चाहिए। इसे चुनाव याचिका के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की वैधता पर सवाल उठाने के आधार के रूप में भ्रष्ट आचरण के आरोप शामिल हैं। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में (6वां) संस्करण) "प्रतिलिपि" को पृष्ठ 336 पर परिभाषित किया गया हैं, जिसका अर्थ है "[ए] प्रतिलेख, दोहरी नकल, या पुनरुत्पादन या एक मूल लेखन, पेंटिंग, उपकरण, या इसी तरह।

सर्वोत्तम साक्ष्य नियम के तहत, एक प्रति तब तक प्रस्तुत नहीं की जा सकती, जब तक कि मूल का लेखा-जोखा न हो जाए। पृष्ठ 1508 पर, "सत्य" शब्द को "[सी] तथ्य के अनुरूप" के रूप में परिभाषित किया गया है; सही; एकदम सही;

वास्तविक; असली; ईमानदार। एक अर्थ में, वह केवल "सच्ची" प्रतिलिपि हैं, जो चीज़ों की वास्तविक स्थिति के अनुरूप हैं। अभिव्यक्ति "सच्ची प्रतिलिपि" परिभाषित किया गया हैं: [ए] सच्ची प्रतिलिपि का मतलब बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब हैं कि प्रतिलिपि इतनी सच्ची होगी कि कोई भी इसे समझ सकता हैं।" वेबस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी (अंतर्राष्ट्रीय संस्करण) में "सच्ची प्रतिलिपि" को

किसी भी दस्तावेज़, रिपोर्ट, आदि की सटीक, शब्दशः प्रतिलेख के रूप में परिभाषित किया गया हैं; विशेष रूप से, जिसे किसी योग्य प्राधिकारी द्वारा सही प्रमाणित किया गया हो"। स्ट्राउडस के न्यायिक शब्दकोश [5 वें संस्करण] [खंड 5) में "सच्ची प्रतिलिपि" को पृष्ठ 2694 पर इस प्रकार परिभाषित किया गया हैं: "एक 'सच्ची प्रतिलिपि' का मतलब बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि नहीं हैं; लेकिन इसका मतलब यह हैं कि प्रतिलिपि इतनी सच्ची होगी कि कोई भी किसी भी संभावना से इसे गलत नहीं समझ सकता हैं। प्रतिलिपि "सच्ची" हैं या नहीं, इसका परीक्षण यह हैं कि क्या मूल से कोई भिन्नता किसी सामान्य व्यक्ति को गुमराह करने के लिए की गई है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक सच्ची प्रतिलिपि मूल के समान या उसका स्थानापन्न, लेकिन बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि हैं। लेकिन कोई भी किसी भी संभावना से यह गलत नहीं समझ सकता कि यह सच्ची प्रतिलिपि नहीं हैं। यह देखा गया हैं कि परीक्षण, जैसा कि पहले कहा गया हैं, यह हैं कि क्या मूल से किसी भिन्नता द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति को गुमराह करने की गणना की गई हैं। जब एक याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने के लिए एक शपथ पत्र के साथ नियुक्त किया जाता हैं, जिसमें आवेदक द्वारा विधिवत शपथ ली जाती हैं, जिसमें उम्मीदवार पर लगाए गए भ्रष्ट आचरण के विभिन्न आरोपों की विधिवत पुष्टि की जाती हैं

और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि कानून का इरादा हैं कि नियमों के नियम 94-ए के साथ पठित फॉर्म 25 में निर्धारित तरीके से इसका पालन किया जाएगा। इसलिए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा हलफनामे का सत्यापन चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए, सवाल यह हैं कि क्या प्रतिवादी को दी गई हलफनामे की प्रति, उसमें मौजूद सत्यापन भाग के बिना (हालांकि मूल हलफनामे में शामिल हैं) "सच्ची प्रति" मानी जा सकता हैं? मिथिलेश कुमार पांडे बनाम बैद्यनाथ यादव एवं अन्य में। (1994)(2) एससीआर 278), वर्तमान स्थिति के अनुरूप, यह सवाल उठा थाः क्या एक चुनाव याचिका की प्रति, हालांकि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत सत्यापित की गई थी, जब इसमें महत्वपूर्ण चरित्र की गलतियाँ थीं, इसे सच्ची प्रति माना जाएगा और क्या अधिनियम की धारा 83(3) की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन किया गया हैं? इस न्यायालय ने, अपीलकर्ता के वकील द्वारा बार-बार पूरे मामले के कानून में उद्धृत किए गए बिन्दुओं को शामिल करने पर विचार करने के बाद, इस प्रकार कहा था:

विषय पर कानून की सावधानीपूर्वक विचार और जांच करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित होते हैं:

(1) कि जहां निर्वाचित उम्मीदवार को दी गई चुनाव याचिकाकर्ता की प्रति में केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी गलतियाँ हैं, जिनका कोई

परिणाम नहीं हैं, याचिका को अधिनियम की धारा 86 के तहत सीधे खारिज नहीं किया जा सकता हैं।

(2) एक सच्ची प्रति का मतलब एक ऐसी प्रति हैं, जो पूरी तरह से और काफी हद तक मूल के समान हैं और जहां नगण्य या न्यूनतम गलतियाँ हैं, अदालत उस पर ध्यान नहीं दे सकती हैं।

(3) जहां प्रतिलिपि में महत्वपूर्ण प्रकृति की महत्वपूर्ण चूक या विसंगतियां शामिल हैं, जिससे निर्वाचित उम्मीदवार के बचाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं, यह नहीं कहा जा सकता हैं कि अधिनियम की धारा 81(3) के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हुआ हैं।

(4) प्रथम दृष्टया, क़ानून "सच्ची प्रतिलिपि" शब्द का उपयोग करता हैं और पर्याप्त अनुपालन की अवधारणा को गंभीर या महत्वपूर्ण गलतियों को शामिल करने के लिए बहुत दूर नहीं बढ़ाया जा सकता हैं, जो एक सच्ची प्रतिलिपि के चरित्र को खत्म कर देता हैं, ताकि निर्वाचित उम्मीदवार को दी गई प्रतिलिपि न दी जा सके। अधिनियम की धारा 81(3) के अर्थ के भीतर एक सच्ची प्रति कहा जा सकता हैं, और

(5) धारा 81(3) के उद्देश्य पवित्र चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा करना हैं, ताकि मतदाताओं के फैसले में खलल न पड़ें, इसलिए उक्त धारा के प्रावधानों की उदार या व्यापक व्याख्या करने के लिए कोई जगह नहीं हैं। चूंकि भ्रष्ट आचरण को पूरी तरह से साबित करना आवश्यक हैं, अस्पष्टता

का तत्व तुरंत चुनाव याचिका को खराब कर देगा।

इसलिए, महत्वपूर्ण और गंभीर प्रकृति की गलतियो से भरी एक सच्ची प्रति चुनाव याचिका को खारिज कर देगी। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सामान्य सिद्धांत संभवतः निर्धारित नहीं किया जा सका।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि हलफनामा चुनाव याचिका का अभिन्न अंग नहीं हैं।

पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त होगा, हमें विवाद में कोई ताकत नहीं दिखती. यह सच हैं कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा बताए जाने पर दोषों को ठीक किया जा सकता हैं। हाई कोर्ट रूल्स के नियम 8 और 9 के मुताबिक, रजिस्ट्रार को खामियां बताने का आदेश दिया गया हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

यह तर्क दिया गया हैं कि प्रतिवादी को किसी भी तरह से गुमराह किया गया या पूर्वाग्रह से ग्रस्त किया गया। दोष इलाज योग्य था। दोषों को ठीक करने के लिए अपीलकर्ता को अवसर दिया जाना चाहिए था। यदि अपीलकर्ता ने सुधार नहीं किया हैं, तो अकेले चुनाव याचिका में उल्लिखित आरोपों के उस हिस्से को हटाना आवश्यक हैं।

चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 86 के तहत खारिज नहीं की जा

सकती, क्योंकि यह धारा 81 के तहत विधिवत प्रस्तुत की गई हैं। यह केवल मुकदमे में, पूर्वाग्रह या प्रतिवादी के कारण हुई चूक या पूर्वाग्रह के सबूत पर किया जाएगा। इस मामले में वह कदम नहीं उठाया गया. इसके समर्थन में, वकील ने इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया, जैसे, मनोहर जोशी बनाम नितिम भाऊराव पाटिल एवं अन्य, 1996(1)एससीसी 169, सुभाष देसाई बनाम शरद जे. राव और अन्य, 1994(पूरक) 2 एससीसी 446, चौ० सुब्बाराव बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद 1964 (6) एससीसी 213, भीकाजी केशाओ जोशी एवं अन्य बनाम बृजलाल नंदलाल बियानी और अन्य, 1955(2) एससीआर 428 से 429, मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौड़ और अन्य, 1964(3) एससीआर 579 और सहोदराबाई राय बनाम राम सिंह अहरवार, 1968(3) एससीआर 13, हमनें सभी उद्धृत निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़ा हैं और संबंधित तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया हैं। किसी भी मामले में वर्तमान प्रश्न नहीं उठा था। सभी मामलों में, सोचा गया कि हलफनामे या चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण के आरोप शामिल थे और सच्ची प्रतियां पेश की गई थी, प्रतियों में चूक भौतिक तथ्यों की नहीं थी, जो चुनाव याचिका या दलीलों का अभिन्न अंग बन जाती हैं। इसलिए, इस न्यायालय ने धारा 86 के तहत आवश्यक जांच के सख्त मानक पर जोर नहीं दिया था।

पुरूषोत्तम बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, अमरावती और अन्य, 1992 एआईआर बाॅम्बे 227,

वर्तमान प्रश्न सीधे खड़ा हो गया था। उस मामले में प्रतिलिपि में महत्वपूर्ण प्रकृति की चूक थी, अर्थात, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन।

उच्च न्यायालय ने माना था कि पर्याप्त अनुपालन की अवधारणा को गंभीर या महत्वपूर्ण गलतियों को नजर अंदाज करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता हैं, जो एक सच्ची प्रतिलिपि के चरित्र को खत्म कर देती हैं, ताकि निर्वाचित उम्मीदवार को दी गई प्रतिलिपि को एक सच्ची प्रतिलिपि नहीं कहा जा सके। हम उपरोक्त दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हैं। नोटरी या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन एक महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो यह आश्वासन देता हैं कि चुनाव याचिकाकर्ता ने नोटरी आदि के समक्ष पुष्टि की थी कि भ्रष्ट आचरण के आरोप वाले बयान को उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही बयान होने के लिए विधिवत और गंभीरता से सत्यापित किया गया था। चुनाव याचिका और उसके समर्थन में दायर हलफनामे में निर्दिष्ट जानकारी; जो दावों को पुष्ट करता हैं, इस प्रकार शपथ पत्र में निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिज्ञान और उसकी प्रयास प्रति की आपूर्ति में भी ऐसी पुष्टि शामिल होनी चाहिए ताकि निर्वाचित उम्मीदवार को यह समझने में गुमराह न किया जाए कि निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष भ्रष्ट आचरण के आरोप की पूरी तरह से पुष्टि

की गई थी या विधिवत सत्यापित किया गया था। उस उद्देश्य के लिए, फॉर्म 25 निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष सत्यापन अनिवार्य करता हैं। उद्देश्य यह प्रतीत होता हैं कि निर्वाचित उम्मीदवार को यह गुमराह नहीं किया गया हैं कि उसका विधिवत सत्यापन नहीं किया गया था। चुनाव याचिका के साथ मूल प्रति दाखिल करने के पर्याप्त अनुपालन की अवधारणा और निर्वाचित उम्मीदवार को सच्ची प्रति के रूप में आपूर्ति की गई प्रति में उसकी चूक को इलाज योग्य अनियमितता नहीं कहा जा सकता। भ्रष्ट आचरण के आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं, जो साबित होने पर, धारा 136 (2) के तहत दोषी ठहराए जाने के अलावा, धारा 8ए के तहत अधिकतम छह साल की अवधि के लिए चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के सार्वजनिक परिणाम होंगे। इसलिए, वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग हैं और निर्वाचित उम्मीदवार को प्रदान की गई सच्ची प्रति में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उचित सत्यापन और सत्यापन शामिल होना चाहिए और चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा सच्ची प्रतिलिपि होने के लिए उसका अपना हस्ताक्षर प्रमाणित होना चाहिए। तथ्यात्मक स्थिति में पर्याप्त अनुपालन के सिद्वान्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं।

यह तर्क कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की ओर से इसकी प्रक्रिया के अनुसार इसे इंगित करने में चूक के कारण चुनाव याचिका को धारा 86

के तहत खारिज नहीं किया जा सकता हैं, को खारिज नहीं किया जा सकता हैं। रजिस्ट्री की ओर से हुई चूक, निर्वाचित उम्मीदवार को यह दलील देने से इनकार करने का आश्वासन नहीं हैं कि हलफनामे का सत्यापन और उसकी सच्ची प्रति होने का प्रमाणीकरण चुनाव याचिका में दलीलों का एक अभिन्न अंग हैं। धारा 81, 83(1)(सी) और 86 को नियमों के नियम 94-ए के साथ पढ़ा जावें और फार्म 25 को एक अभिन्न योजना के रूप में पढ़ा जावें। ऐसा पढ़ने पर, यदि न्यायालय को निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति पर चुनाव याचिका की पोषणीयता के बारे में पता चलता हैं, तो न्यायालय को प्रश्न पर विचार करना होगा और प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेना होगा। यदि न्यायालय इसे बरकरार नहीं रखता हैं तो मुकदमा चलाने की आवश्यकता उत्पन्न होगी। यदि न्यायालय प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखता हैं, तो चुनाव याचिका जल्द ही खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि न्यायालय के पास इसे खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता हैं।

यह सच हैं कि श्रीमती शिप्रा के मामले में यानी 1994 के सी.ए.नंबर 6359 में, उनके द्वारा एक और तर्क उठाया गया था कि उनके नामांकन की अस्वीकृति कानून में अमान्य थी।

उच्च न्यायालय ने माना हैं कि भले ही घोषित चुनाव परिणाम की वैधता पर सवाल उठाने के लिए अधिक आधार उठाए गए हों और यदि

नियम 94-ए के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 83(1)(सी) की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया हो, तो पूरी याचिका बर्खास्त होती। हमारा दृढ़ मत हैं कि यह दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से सही नहीं हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित हैं कि याचिका के केवल वे ही हिस्से जिनमें भ्रष्ट आचरण के आरोप हैं और जो नियम 94-ए और धारा 83(1) के साथ पढ़े गए फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें ही हटा दिया जाना चाहिये और अन्य स्वतंत्र होना चाहिये। मुद्दों पर प्रयास करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता हैं। इस मामले में, हालांकि उसके नामांकन की अस्वीकृति की वैधता पर अपीलकर्ता द्वारा सवाल उठाया गया था, ऐसा प्रतीत होता हैं कि उच्च न्यायालय में इसे गंभीरता से प्रचारित नहीं किया गया था और अपीलकर्ता के वकील द्वारा उच्च न्यायालय में भ्रष्ट आचरण और दोष के निवारण पर तर्क का मुख्य जोर दिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, हमारा मानना हैं कि अनुचित अस्वीकृति या नामांकन के आधार पर अपीलकर्ता को चुनाव लड़ने से रोकने का सवाल गंभीरता से विचार करने के लिए नहीं उठता हैं। पूरी चुनाव याचिका केवल भ्रष्ट आचरण के आरोप पर ही टिकी हुई थी। नतीजतन, जब चुनाव याचिका को हलफनामे की असली प्रति जो चुनाव याचिका का अभिन्न अंग हैं, में भौतिक दोष के कारण सुनवाई योग्य नहीं माना गया, तो चुनाव याचिका को खारिज करने को गलत नहीं ठहराया जा सकता हैं।

अन्य अपीलों में भ्रष्ट आचरण के आरोपों के अलावा किसी अन्य आधार की पैरवी नहीं की गई। इन परिस्थितियों में, हमारा मानना हैं कि विद्वान न्यायाधीशों ने हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई कानूनी त्रुटि नहीं की हैं।

तदनुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

भरूचा जे.

मैं अपने विद्वान भाई के.रामास्वामी जे. के फैसले और आदेश से सम्मानजनक सहमत हूूॅ। मैं अपने कारणो को संक्षेप में इस प्रकार बताऊंगाः

17. जो प्रश्न उठाया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय के पिछले निर्णयों से संकेत मिलता हैं, वह यह हैंः क्या चुनाव याचिका की सच्ची प्रति होने का दावा करने वाला दस्तावेज़ किसी विशेष सामग्री में गुमराह करता हैं? अपीलकर्ता (चुनाव याचिकाकर्ता) द्वारा प्रतिवादी(सफल उम्मीदवार) को दी गई चुनाव याचिका की "सच्ची प्रति" यह नहीं दिखाती हैं कि भ्रष्ट आचरण के अपने आरोपों का समर्थन करने वाले अपीलकर्ता के हलफनामें में विधिवत शपथ ली गई थी या पुष्टि की गई थी। जहां भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया जाता हैं, चुनाव याचिकाकर्ता को निर्धारित प्रारूप में एक हलफनामा देकर आरोप का समर्थन करना होगा। शपथ पत्र में

कानून द्वारा आवश्यक तरीके से शपथ ली जानी चाहिए या पुष्टि की जानी चाहिए, अन्यथा यह शपथ पत्र नहीं हैं। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को सौंपी गई चुनाव याचिका की सच्ची प्रति होने का दावा करने वाले दस्तावेज ने यह आभास दिया कि भ्रष्ट आचरण के अपने आरोपों का समर्थन करने वाले अपीलकर्ता के हलफनामें में शपथ या पुष्टि नहीं की गई थी और इसलिए, कोई भी हलफनामा नहीं था; इसने एक खास मामले में गुमराह किया और इसकी आपूर्ति, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना, चुनाव याचिका के लिए घातक थी।

परिपूर्नन, जे.

18. मैं अपने विद्वान भाइयों से आदरपूर्वक सहमत हूं कि अपीलें खारिज कर दी जानी चाहिए।

19. अपील में प्रासंगिक तथ्य मेरे विद्वान भाई रामास्वामी जे. के फैसले में बताए गए हैं, प्रश्न के महत्व को देखते हुए, मैं निम्नलिखित जोड़ूंगा:

20. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 81, 83 और 86, अपीलों के इस बैच में व्याख्या की मांग करती हैं। उक्त वैधानिक प्रावधानों को उपयोगी रूप से उद्धृत किया जा सकता हैं।

धारा 81

81. याचिकाओं की प्रस्तुति. -(1) किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने वाली एक चुनाव याचिका धारा 100 और धारा 101 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या किसी भी निर्वाचक द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं। निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तारीख पैंतालीस दिन, लेकिन उससे पहले नहीं, या यदि चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव की तारीखें या अलग-अलग हैं, तो उन दो तारीखों में से बाद की तारीखें।

स्पष्टीकरण। -इस उपधारा में, "निर्वाचक" का अर्थ उस व्यक्ति से हैं जो चुनाव में मतदान करने का हकदार था, जिससे चुनाव याचिका संबंधित हैं, चाहे उसने ऐसे चुनाव में मतदान किया हो या नहीं।

(3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उसकी उतनी ही प्रतियां संलग्न की जाएंगी, जितने याचिका में उल्लिखित उत्तरदाताओं के हैं, और ऐसी प्रत्येक प्रति को याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत याचिका की सच्ची प्रति के रूप में सत्यापित किया जाएगा। (जोर दिया गया)

धारा 83.

83 याचिका की विषयवस्तु. -(1) एक चुनाव याचिका -

(ए) में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता हैं;

(बी) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसे भ्रष्ट आचरण करने वाले कथित दलों के नाम और ऐसे प्रत्येक आचरण के आगे की तारीख और स्थान का यथासंभव पूरा विवरण शामिल होगा।

(सी) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और दलीलो के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगाः

इसके होते हुए भी कि जहां याचिकाकर्ता किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता हैं, तो याचिका के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में एक हलफनामा भी संलग्न किया जाएगा।

(2) याचिका की किसी अनुसूची या परिशिष्ट पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान तरीके से सत्यापित किए जाएंगे।

(जोर दिया गया)

धारा 86(1)

86. चुनाव याचिका का परीक्षण-(1) उच्च न्यायालय उस चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती हैं।

21. इस न्यायालय के असंख्य निर्णय हैं, जिन्होंने उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का अर्थ लगाया हैं, उन सभी का उल्लेख करना शायद ही आवश्यक हो। नवीनतम निर्णयों में से एक एफ.ए.सापा और अन्य बनाम वी. सिंगोरा और अन्य, 1991(3)एस.सी.सी. 375, धारा 83(2) के साथ-साथ धारा 83(1) के प्रावधान पर एक नजर डालने से पता चलेगा कि धारा 83(1) के प्रावधान में सन्दर्भित हलफनामा भी चुनाव याचिका का हिस्सा हैं। चुनाव याचिका वास्तव में एक दस्तावेज हैं, जिसमें दो भाग शामिल हैं, एक चुनाव याचिका और दूसरा अधिनियम की धारा 83(1) के परन्तुक में सन्दर्भित हलफनामा हैं। इसलिए, धारा 83 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 81(3) के तहत दायर की जाने वाली चुनाव याचिका की प्रति में हलफनामे की एक प्रति शामिल होगी। देखेंः एम. कमालम बनाम डॉ. वी.ए. सैयद मुहम्मद, ए.आई.आर.(1978) एस.सी. 840(844)

22. काजी, जे. पुरूषोत्तम बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, अमरावती एवं अन्य, ए.आई.आर.1992 बाॅम्बे 227 और अन्य में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के साथ-साथ अन्य निर्णयों और 1990 की चुनाव याचिका संख्या 2 में बाॅम्बे उच्च न्यायालय के एक असूचित निर्णय का उल्लेख करने के बाद यह माना गया कि प्रति पर नोटेरी के समर्थन की अनुपस्थिति चुनाव याचिका के साथ संलग्न हलफनामा प्रति को अधिनियम की धारा 81(3) के अनुरूप नहीं बनाता हैं, और उक्त चूक के लिए चुनाव

याचिका खारिज की जा सकती हैं।

23. मेरी राय में, उपरोक्त निर्णय कानून को सही ढंग से निर्धारित करता हैं, और यहां पूरी तरह से लागू होता हैं। विशेष रूप से, 1990 की चुनाव याचिका संख्या 2 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के असूचित निर्णय में काजी, जे. के फैसले के पैराग्राफ संख्या 12 में उद्धृत निम्नलिखित टिप्पणियां शिक्षाप्रद हैं और उक्त निष्कर्ष तक पंहुचने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती हैं। अवलोकन निम्नलिखित प्रभाव वाले हैंः

50. हालाँकि, एक प्रश्न पर विचार किया जाना बाकी हैं और वह यह हैं कि क्या नोटरी द्वारा "मेरे समक्ष पुष्टि की गई और हस्ताक्षरित", पृष्ठांकन की प्रति, नोटरी का पदनाम और उस प्रतिज्ञान के संबंध में मुद्रांकित पृष्ठांकन जो उसने उस समय किया था। हलफनामा बनाना, दस्तावेज़ के आवश्यक और अनिवार्य भाग थे और यदि इन्हें प्रस्तुत प्रति से हटा दिया जाता हैं, तो जो प्रतिलिपि सुसज्जित हैं, वह अधूरी हो जाएगी, और दोष इतना स्पष्ट होगा कि अनुमान को नकारात्मक बना देगा। प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। जब फॉर्म नंबर 25 एक विशेष फाॅर्म निर्धारित करता हैं और उस हलफनामें की प्रति प्रस्तुत की जानी हैं, तो मुझे ऐसा लगता हैं कि प्राधिकारी का समर्थन जिसके समक्ष प्रतिज्ञान किया गया था, उसके आधिकारिक पदनाम और मुद्रांकित समर्थन के साथ, भी आवश्यक हैं और उनके बिना प्रतिलिपि को सच्ची प्रतिलिपि नहीं माना जा सकता। यह

केवल हलफनामें की सामग्री नहीं हैं जो दस्तावेज में पवित्रता लाती हैं, बल्कि प्रतिज्ञान भी किया गया हैं और प्रतिज्ञान के बिना यह बिल्कुल भी हलफनामा नहीं हो सकता हैं। मैं श्री बोबडे की इस दलील से प्रभावित नहीं हूँ कि ये समर्थन केवल औपचारिक थे, क्योंकि धारा 83 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत जो आवश्यक हैं, वह एक हलफनामा हैं और प्रतिवादी के लिए यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि क्या, वास्तव में, सामग्री को मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष शपथ दिलायी गई, पुष्टि की गई और हस्ताक्षरित किए गए या जिस व्यक्ति की उपस्थिति में प्रतिज्ञान की शपथ ली गई थी, उसे शपथ दिलाने का अधिकार था। प्रतिवादी यह बताने की स्थिति में नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया हैं कि उसने शपथ दिलाई थी, वह अस्तित्व में नहीं था या उसके पास शपथ दिलाने का कोई अधिकार नहीं था या कथित दस्तावेज पर हस्ताक्षर और समर्थन किया गया था, कथित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए फर्जी थे। यदि हलफनामें की प्रतियां विश्वसनीय नहीं हैं और इनमें ये समर्थन शामिल नहीं हैं, तो प्रतिवादी का एक मूल्यवान अधिकार छीन लिया जाता हैं और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो समर्थन की प्रति पूरा करेगी, यह नहीं कहा जा सकता हैं कि यह भाग शपथ पत्र का अभिन्न अंग नहीं होगा। चूंकि ये विवरण हलफनामें का एक अभिन्न हिस्सा हैं, इसलिए उस हिस्से के बिना एक प्रति प्रस्तुत करना पूरी प्रतिलिपि प्रस्तुत करना नहीं होगा, और उस स्थिति में, केवल इसलिए कि निर्वाचित उम्मीदवार ने यह समर्थन किया हैं

कि यह एक सच्ची प्रति हैं, इसे एक सच्ची प्रति नहीं माना जा सकता हैं, जिस उद्देश्य को पूरा किया जाना हैं, उस पर विचार करते हुए, मुझे नहीं लगता कि चूक को महत्वहीन माना जा सकता हैं।

(जोर दिया गया)

24. सम्मानपूर्वक, मैं उक्त टिप्पणियों को अपनी टिप्पणी के रूप में अपनाऊंगा। अपीले खारिज किये जाने योग्य हैं।

वी.एस.एस. अपील खारिज की गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सुनील कुमार ओझा** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)